23.06.2018

इंडिया टुडे एग्रो समिट एवं अवाईस 2018

देवियों और सज्जनों।

मुझे ख़ुशी है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने आज कृषि के क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा और अवाईस देने के लिए 'इंडिया एग्रो समिट एवं अवाईस 2018' का आयोजन किया है, जो इस श्रंखला का दूसरा आयोजन है।

2. साथियो, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। ग्रामीण क्षेत्र में जन-जीवन का आर्थिक स्त्रोत व रोज़गार का प्रमुख ज़रिया होने के साथ साथ आज विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम बनी कृषि को देश की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

3. किसी भी देश का विकास उसके कृषि क्षेत्र के विकास के बिना अधूरा है। भारतीय कृषि देश की जीवन रेखा हैं और किसान देश के "अन्नदाता"। वो लोगों को भोजन देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, घरों के लिए ईंधन देते हैं और उद्योगों को कच्ची सामग्री देते हैं। देश की खाद्य सुरक्षा का ज़िम्मा भी हमारे किसान भाईओं के कन्धों पर ही है और उन्होंने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया भी है। इसीलिए देश की खाद्य सुरक्षा को सतत आधार पर सुनिश्चित करने का श्रेय हमारे किसानो को ही जाता है । आज वस्तुस्तिथि यह है कि भारत न केवल बहुत से कृषि उत्पादों में आत्म निर्भर व् आत्म संपन्न है वरन बहुत से उत्पादों का निर्यातक भी है।अतः यह कहना समीचीन होगा कि कृषि के विकास, समृद्धि व उत्पादकता पर ही देश का विकास व सम्पन्नता निर्भर है।

4. भारत गांवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में कृषि का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है इसी लिए भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी दी गई है।

5. जब हम सरकार में आए थे तो हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। कृषि क्षेत्र में निवेश कम हो रहा था एवं क्लाइमेंट चेंज के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होना संभावित था। कृषि के क्षेत्र में विकास तो हो रहा था पर किसानो का अपना विकास सिकुड़ रहा था। खेती में होने वाली लागत की अपेक्षा कम आय उनकी कृषि के प्रति रूचि को दिन प्रति दिन घटा रही थी। दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों ने इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2014 में जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला तो हमने इन आधारभूत समस्याओं का आंकलन करके दूरगामी प्रभाव वाली योजनाओं को लागू किया जिससे कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके । प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाही में हमने यह निर्णय लिया कि हम अपनी योजनाओं को इस तरह से लागू करेंगे कि किसानों को साथ लेते हुए वर्ष 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो सके।

6. आपने हाल ही में दिनांक 20 जून 2018 को आयोजित प्रधानमंत्री जी का किसानो से संवाद को सुना होगा जिसमे उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के किसानो से सीधे संवाद किया, जिसमे देश के किसानो ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को बताया की उन्हें पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार की अनुकूल नीतियों, कारगर योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन से किस प्रकार लाभ हुआ।

7. पिछले 4 वर्षो के दौरान ज़मींन के रख रखाव से लेकर; उत्तम क्वालिटी के बीज मुहैया करवाने; बिजली पानी से लेकर बाज़ार उपलब्ध करवाने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कार्य करने का

भरसक प्रयास इस सरकार ने किया है। इस कार्य को सही अंजाम देने के लिए सरकार द्वारा जिन 4 बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जा रहा है, वो है -

I. किसान की लागत को कम से कम कैसे किया जाये

II. किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले

III. किसान की उपज की बर्बादी को कैसे रोका जाये

IV. किसानी के अलावा आमदनी के वैकल्पिक स्त्रोत मुहैया करवाए जाये

8. यदि देखा जाये तो आज मिशन मोड में इन चारो मुद्दों पर कार्यवाही की जा रही है । सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिये ड्रिप व स्प्रिंकलर इरीगेशन जैसी कुशल तकनीको का प्रसारण किया जा रहा है । भूमि की उर्वरता को सतत बनाए रखने के लिये ''सॉयल हेल्थ कार्ड' जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान सरकार की पहलों में कृषि से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना- ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' पूरे देश में लागू की गयी।

9. इन सब योजनाओं के चलते पिछले 48 महीनो में कृषि के क्षेत्र में अभूत पूर्व प्रगति दर्ज हुई है। नतीजन वर्ष 2017-18 में खाद्यान उत्पादन 279.51 मि. टन हुआ है जबकि वर्ष 2010 से 14 का औसत उत्पादन 255.59 मि. टन था जोकि 9.35 % अधिक है। दलहन के क्षेत्र में भी औसत उत्पादन में 10.5% एवं बागवानी के क्षेत्र में 15% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसी क्रम में यदि 4 वर्षों बनाम 4 वर्षों की तुलना करें तो 26.01% की वृद्धि है। नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य पालन के क्षेत्र में 26.01% वृद्धि एवं पशु पालन व दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 23.69% की वृद्धि दर्ज की गई तथा अंडा उत्पादन में 25.19% की वृद्धि हुई। नीम कोटेड यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड,

मैकेनाइजेशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) से संसाधनों का बेहतर उपयोग से कृषि की लागत में कमी हुई है। परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनई) के तहत वर्षा सिंचित और पर्वतीय क्षेत्रों में निरंतर उत्पादन करने में आड़े आने वाली समस्याओं का समाधान करना संभव हुआ है।

10. आज गर्व के साथ कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार के 48 महीनों में परम्परागत कृषि विकास योजना प्रारम्भ कर 947 करोड़ की राशि से 10,000 समूहों (क्लस्टर) का गठन भी कर दिया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन प्रारम्भ किया गया है जिसके तहत 225.96 करोड़ की राशि से किसानों को, किसान उत्पादक संघों व किसान हितधारक समूहों को जोड़ा जा चुका है।----------

11. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कृषि क्षेत्र के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की गई है। 2010 से 14 खरीफ मौसम की तुलना में 2014 से 18 में ऋणी व गैर ऋणी किसानों के कुल व्याप्ति में 63.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2010 से 14 की रबी मौसम की तुलना में 2014 से 18 में ऋणी किसानों के कुल व्याप्ति में 38.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के व्याप्ति में 102.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका लाभ कई राज्यों में जहां आपदा आई वहीं के किसानों को मिला है, जिसका विवरण साथ में है।

12. ई-नाम के प्रयोजन से इंटीग्रेटिड राष्ट्रीय कृषि बाजार की संरचना बनाई गई है जिससे कि किसानों को पारदर्शी तरीके से अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। वर्तमान सरकार के 48 महीनों के दौरान राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) 170.87 करोड़ की राशि से राज्यों की 585 विनियमित थोक

मंडियों को एक ई-प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इस पोर्टल पर 98,71,956 किसानों; 1,09,725 व्यापारियों और 61,220 कमीशन एजेंटों को पंजीकृत किया जा चुका है। अगले दो वर्षों में 415 मंडियों को जोड़ा जाएगा। देश के लगभग 22,000 कृषि मंडियों के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि का कोष भी प्रस्तावित किया गया है।

13. आज देश में चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल दिख रहा है। जहाँ एक तरफ यूपीए सरकार के पांच वर्षों में कृषि मंत्रालय का बजट 1 लाख 21 हजार 82 करोड़ था वहीं मोदी सरकार में बढ़कर 2 लाख 11 हजार 694 करोड़ हो गया। बजटीय आवंटन के अलावा किसान उत्पादक संगठनो, कृषि संभार तंत्र, प्रसंकरण सुविधाओं और व्यवसायिक प्रबंधन से जुड़े कार्यो के संवर्धन के लिए ऑपरेशन ग्रीन; पूंजीगत निवेश के लिए एग्री मार्किट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, माइक्रो सिंचाई फंड, एक्क्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड, डेयरी प्रसंकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड (डी.आई.डी.) तथा समेकित भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कट विकास कोष जैसे पूंजीगत निवेश भी किये गए है । यह सभी प्रयास कृषि को एक उद्यम के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रहे है ।

14. समर्थन मूल्य - सभी अधिसूचित जिंसों की लागत 1.5 गुना की घोषणा कर दी गई है। नीति आयोग ने राज्य सरकारों एवं कृषि मंत्रालय से बात-विमर्श कर खरीफ के बाद समर्थन मूल्य जब नीचे आये तो किसानों को इसका लाभ कैसे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। कई जिंसों के समर्थन मूल्य 1.5 गुना था किन्तु यूपीए सरकार के 4 वर्षों में दलहन,

तिलहन पर 8 लाख 4 हजार 923 मैट्रिक टन व मोदी सरकार के 4 वर्षों में 64 करोड़ 13 लाख 20 हजार 994 मैट्रिक टन की खरीद हुई।

- कई जिंसों के आयात शुल्क भी काफी बढ़ाये गये है, इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है।

15. कृषि से जुड़े संबध क्रियाकलापों के माध्यम से किसानो की आय वृद्धि की दिशा में भी अभूतपूर्व प्रगति दर्ज हुई है। फसल के साथ खेती की ज़मीन पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए 'हर मेड पर पेड़' स्कीम वर्ष 2016-17 में शुरू की गयी थी और इसे उन राज्यों में लागू किया जा रहा है, जहाँ इमारती लकड़ी ले जाने के लिए परिवहन नियमो को अधिसूचित कर दिया गया है। कृषि आय के अनुपूरक के रूप में बांस के मूल्य श्रंखला आधारित समग्र विकास के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा भी की गई है, जो किसान की आय वृद्धि में एक बेहतरीन योगदान का ज़रिया बनेगा। बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश 2017 की घोषणा की गई, जिसमें बांस को वृक्ष न मानकर घास माना जाएगा।

16. मधु मक्खी पालन एक और ऐसा सहायक धंधा है, जो किसानो की आय के साथ साथ फसलों के प्राकृतिक परागण में भी सहायक है। आज कृषि की लगभग 100 प्रजातियों में से 70% फसल प्रजातियां, जो विश्व की 90 % जनसँख्या का भोजन है, उनके परागण का काम यह मधु मक्खियाँ करती है। सरकार का मानना है कि मधु मक्खी पालन तथा इस जैसे अन्य आय स्रोतों के विकास पर ज़ोर देने की आवश्यकता है। मधुमक्खी पालन क्रांति के अंतर्गत भारी संख्या में किसानो, मधुमक्खी पालको को वैज्ञानिक

मधुमक्खीपालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है और शहद समितियों मधुमक्खी पालको, मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजीकरण भी किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में एक जिले के विकास के बारे में, एक रोल मॉडल के रूप में समेकित मधुमक्खीपालन विकास केंद्र, की स्थापना भी की जा रही है।

17. डेयरी एवं मत्सिकी विकास के लिए भी राष्ट्रीय डेयरी योजना- 1 (एन.डी.पी.-1), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) और डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम व् नीली क्रांति जैसे कार्यक्रम किर्यान्वित किये जा रहे है जिनका पूरा पूरा लाभ किसान भाई उठा सकते है । हमने देसी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत 31 मार्च 2018 तक राज्यों में 546.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में सरकार के 4 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक खर्चा पिछली सरकार के 10 वर्षो के खर्च 95.61 करोड़ से बढ़ कर 407.58 करोड़ हो गया है औसत मछली उत्पादन भी 7.8 मिलियन मीट्रिक टन से 11.26 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। बागवानी के क्षेत्र में हमने रिकार्ड 307 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया है।

18. कृषि अनुसंधान, शिक्षा व तकनीकी प्रसार से अधिक युवा अब कृषि व संबंधित क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। कृषि शिक्षा में युवाओं का आकर्षण बढ़ाने हेतु कृषि संबंधी विषयों की डिग्रीयों को व्यवसायिक डिग्री घोषित किया गया है। साथ ही 1100 करोड़ रूपये की राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना प्रारम्भ की गई है। छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति रू 1000 से

बढ़ाकर रू 2000 की गयी है तथा स्टूडेंट रेड्डी योजना के तहत सभी छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली अध्येतावृति रू 750 से बढ़ाकर रू 3000 प्रतिमाह की गयी। फसलों की उत्पादकता एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों की 795 किस्में विकसित की गई हैं। पोषक तत्वों से समृद्ध (बायो फोरटिफाइड) 20 से अधिक फसलों की प्रजातियां विकसित की गई हैं। 48 महीनों की मोदी सरकार में कृषि विस्तार के क्षेत्र में पहली बार निम्न योजनाएं चलाई गईं :

• मेरा गांव - मेरा गौरव : इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों से 4-4 वैज्ञानिकों के समूह 5 चयनित गांवों को अपनाकर वहां सीधे किसानों का विभिन्न तरीकों व किस्मों पर मार्गदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम को वर्तमान सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है

• आर्या : युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित कर उनकी अभिरूचि बनाए रखने के लिए इस योजना को वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ किया गया। जिसमें ग्रामीण युवाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है

• फार्मर फर्स्ट : समग्र ग्राम विकास के लिए इस कृषि मॉडल को वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किया गया। जिसके माध्यम से कई किसान परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय के साथ किसानों के कौशल विकास कार्यक्रम को तेज करने हेतु एक समझौता किया गया।

19. किसानो की समस्यायों के अनुकूल नीति परिवर्तन तथा कार्यक्रमों के उचित किर्यान्वन के अतिरिक्त सरकार का यह प्रयास भी है कि किसानो को सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी भी मिलती रहे। इसी आशय से

हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पूरे देश में 2 मई 2018 को तमाम पंचायतो एवं बलाकों में 'किसान कल्याण कार्यशाला' का आयोजन किया गया जिनमे किसानो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1 जून से 31 जुलाई के बीच देश के सभी महत्वाकांक्षी जिलो में किसान कल्याण अभियान चलाया जा रहा है जिसमे हर जिले के 25 गावों में किसानो को परिशिक्षित किया जा रहा है ।

20. भारत आज विश्व की तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में कारोबार करना अब पहले से कहीं अधिक आसान है। आज हम गौरवान्वित है कि सरकार की नीतिगत योजनायें के साथ-साथ उन्हें किर्यान्वन में लाने के समयबद्ध प्रयास भारत को कृषि क्षेत्र मे विश्व के अग्रणी देशो की कतार में सबसे आगे रखने मे कारगर होगा और हम किसानो की आय नियत लक्ष्य अनुसार दोगुनी करने में अवश्य सफल होंगे।

धन्यवाद

कुछ राज्यों जहाँ मौसम प्रतिकूल था मे कुल प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध बीमा दावों का भुगतान अधिक किया गया है :

खरीफ 2016 मौसम

राज्य	कुल प्रीमियम (रूपया)	कुल बीमा दावा (रूपया)	प्रीमियम के विरुद्ध कुल दावा का प्रतिशत
केरल	8.58 करोड़	17.96 करोड़	210%
कर्नाटक	873.35 करोड़	1165.06 करोड़	133%
आंध्र प्रदेश	699.90 करोड़	652.93 करोड़	93%

रबी 2016-17

राज्य	कुल प्रीमियम (रूपया)	कुल बीमा दावा (रूपया)	प्रीमियम के विरुद्ध कुल दावा का प्रतिशत
तमिलनाडू	1208.66 करोड़	3286.84 करोड़	273%
आंध्र प्रदेश	122.81 करोड़	254.65 करोड़	207%

खरीफ 2017 मौसम

राज्य	कुल प्रीमियम (रूपया)	कुल बीमा दावा (रूपया)	प्रीमियम के विरुद्ध कुल दावा का प्रतिशत
छत्तीसगढ़	317.19 करोड़	1159 करोड़	366%
हरियाणा	290.39 करोड़	465 करोड़	160%
मध्यप्रदेश	3765.92 करोड़	5232 करोड़	139%
उड़ीशा	837.40 करोड़	1603 करोड़	191%